RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 20 MAY TO 26 MAY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 39 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

मझोले उद्यमों की परिभाषा में और बदलाव किए जाएंगे: एमएसएमई
Page 3

EPF अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू
Page 4

जर्मनी की फुटवियर कंपनी चीन से आगरा लाएगी अपना कारखाना
Page 7

editoria!

राज्यों पर दारोमदार

तमाम आशंकाओं और आपत्तियों के बीच भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलना है। इससे पहले कई तरफ से यह बात उठी थी कि लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के फैलाव को बेकाबू होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब देश इस स्थिति में पहुंच रहा है कि लॉकडाउन से होने वाला नुकसान इसके फायदे को बहुत पीछे छोड़ सकता है। आर्थिक गतिविधियों का ठप पड़े रहना न सिर्फ करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना सकता है, बल्कि समूची व्यवस्था के सामने गंभीर खतरे खड़े कर सकता है। संभवतः इसीलिए लॉकडाउन का चौथा चरण घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने साफ कहा कि सारे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के साथ ही इस चरण में ज्यादा जोर आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और जनजीवन को सामान्य बनाने पर रहेगा। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई छूटें घोषित की हैं, साथ ही आगे की छूटों के बारे में फैसला राज्य सरकारों और जिला प्रशासन पर छोड़ा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को और कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। राज्य सरकारें जमीनी स्थितियों से बेहतर ढंग से वाकिफ होती हैं, इसलिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीमारी के फैलाव के खतरों और आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त फैसला वे ज्यादा आसानी से कर सकती हैं। इसका असर भी पहले दिन से ही दिखने लगा। दिल्ली में एम्स अस्पताल ने इसी सप्ताह ओपीडी खोलने का फैसला करते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों से कैब और निजी वाहनों के आने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के अंदर बस, ऑटो और निजी वाहनों के चलने की इजाजत दे दी है, साथ ही उन्हें पैसेंजरों की संख्या कम रखने और अन्य सावधानियां बरतने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। राज्यों पर फैसला छोड़ने का एक मतलब यह भी है कि इस चरण में सबके बीच सामंजस्य बनाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसका संकेत पहले ही दिन कर्नाटक सरकार के उस फैसले से मिला जिसमें उसने साफ कहा कि चार राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से लोगों के उसकी सीमा में आने पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चारों राज्य इसे अपने खिलाफ उठाया गया कदम मानकर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना से निपटने और आर्थिक मंदी से बचने की दुतरफा चुनौती से जूझने का हमारा संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। बेहतर होगा कि लोकल लेवल पर बीमारी से सर्वश्रेष्ठ तरीके से लड़ाई जारी रखते हुए भी हम अपने नजरिये को राष्ट्रीय बनाए रखें। यह केंद्र सरकार के राजनीतिक कौशल का इम्तहान भी है क्योंकि राज्यों में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी अंततः उसी की है।

बंद उद्योगों को लाखों के बिल

■औद्योगिक संगठनों का ई- धरना आंदोलन को आईपीपीएफ का समर्थन ■एआईएमपी के नेतृत्व में जुटेगें प्रदेश के 150 औद्योगिक संगठन ■ विद्युत बिल के फिक्स चार्ज, न्यूनतम युनिट्स और पॉवर फैक्टर का विरोध

(विस्तृत समाचार पृष्ठ 4-5 पर)

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से सबसे बडी त्रासदी के रूप में फैल रही है। भारत भी इस महामारी से अछुता नही है, पिछले 60 दिनों से उद्योग कारखाने बंद पडे है। उद्योगों में विद्युत उपभोग नही के बराबर है लेकिन विद्युत वितरण कंपनियों के तानाशाही रवैये के कारण 100 युनिट विद्युत उपभोग पर भी लाखों के बिल थमाये जा रहे है। विद्युत कंपनियों के द्वारा वसूले जा रहे फिक्स चार्ज, न्यूनतम मिनिट्स और पॉवर फैक्टर का विरोध पुरे प्रदेश में किया जा रहा है। अब इसके विरोध में प्रदेश के 150 से अधिक औद्योगिक संगठन ई-धरना दे कर करेंगे। इसके लिए इंदौर का औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के संयोजन में पुरे प्रदेश के औद्योगिक संगठन 21 मई को सुबह 11 बजे ई-धरना देगें। प्रदेश व्यापी इस औद्योगिक आंदोलन के संयोजक और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र के अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया ने बताया कि लॉकडाउन के इस दौर में जुझ रहे उद्योगों के हित में सभी औद्योगिक संगठनों का समर्थन मिला है।

केन्द्रीय करों से राज्यों को मिले 46,039 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के 15,340 करोड रुपये जारी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से की 46,038.70 करोड़ रुपये की मई माह की किस्त को मंजूरी दे दी है। वहीं, सूत्रों ने बताया कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को इस वित्त वर्ष में अब तक 15,340 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "मई माह के लिये राज्यों के हिस्से की जारी की गई किस्त अप्रैल के ही समान है। इसकी गणना सरकार की मौजूदा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर नहीं बल्कि वर्ष 2020- 21 के बजट अनुमानों के आधार पर की गई है।" इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों के राजस्व की रक्षा करने के साथ ही उनकी नकदी जरूरतों को पूरा करना है। वित्त मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि जहां तक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात है 2019-20 में नवंबर 2019 तक राज्यों को 1,20,498 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं जबकि इससे पिछले वर्ष 2018-19 में पूरे साल के दौरान 69,275 करोड़ रुपये जारी किये गये। उससे पहले 2017- 18 में 41,146 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये। जीएसटी प्रणाली एक जुलाई 2017 से लागू है। इस साल के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने विभाजित होने वाले राजस्व पूल में से राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा नपवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये एक प्रतिशत राशि तय की गई है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया था। वित्त मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा है, "वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के लिये मई माह की किस्त के तौर पर 46,038.70 करोड़ रुपये मंजूरी के आदेश जारी किये हैं।" इस राशि में से आंध्र प्रदेश को 1,892.64 करोड़ रुपये, असम को 1,441.48 करोड़ रुपये, गुजरात को 1,564.4 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिये 3,461.65 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 8,255.19 करोड़ रुपये, केरल को 894.53 करोड़ रुपये और बिहार के लिये 4,631.96 करोड़ रुपये जारी होंगे। हरियाणा के हिस्से में 498.15 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये, झारखंड को 1525.27 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 3630.60 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2824.47 करोड़ रुपये मिलेंगे।

MSMEs के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट का स्वागत पर क्रेडिट सप्लाई चेन हो 100% कॉन्टैक्टलेस

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल में वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ उपायों की घोषणा की गई है। इन उपायों का उद्देश्य, फ्रेश कैश डालकर, मोरेटोरियम के साथ कोलैटरल-फ्री लोन देकर और उनके टैक्स अनुपालन पश्चाताप को कम करके सुयोग्य MSMEs के लिक्विडिटी प्रॉब्लम को कम करना है।

क्रेडिट सप्लाई चेन को 100% कॉन्टैक्टलेस बनाना होगा

कोरोनावायरस संकट ने वैल्यू चेन्स को तबाह कर दिया है और लॉकडाउन के माध्यम से बिज़नस पर बहुत बुरा असर डाला है। इस लिक्विडिटी सपोर्ट के जरिए बिज़नस अब नए सिरे से काम करने और बहुत जल्द जॉब क्रिएशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक समस्या है जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में कंपनी के साथ आमने-सामने बात करके लोन लेना पड़ता है और ऑफलाइन हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन कोरोना महामारी से ग्रस्त संसार में, अब यह सुरक्षित नहीं है। इसलिए लिक्विडिटी सम्बन्धी उपाय करने के साथ-साथ हेल्थ रिस्क के नजरिए से यह देखना भी जरूरी है कि एमएसएमई को वह लिक्विडिटी कैसे मिलेगी। इसके लिए क्रेडिट सप्लाई चेन को 100% कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल बनाना होगा।

डिजिटल तरीके से अपना KYC पूरा करने की इजाजत

मौजूदा समय में 60,000 रुपये से बड़े लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रॉसेस को पूरा करने के लिए बैंक या कर्जदाता से आमने-सामने मिलना पड़ता है। इसका खर्च उपभोक्ताओं के सिर पर आने के अलावा इस प्रॉसेस में अब जानलेवा फ्लू पकड़ने का खतरा भी है। इसलिए MSMEs को अपनी डिवाइस से लोन के लिए अप्लाई करने, अपने दस्तावेज अपलोड करने और डिजिटल तरीके से अपना KYC पूरा करने की इजाजत देनी चाहिए। इस प्रॉसेस में बैंक के साथ आमने-सामने मिलकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह प्रॉसेस डिजिटल तरीके से पूरा होता है। इसके लिए टेक्नॉलजी है लेकिन इस टेक्नॉलजी का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए KYC फ्रेमवर्क में कुछ संशोधन की जरूरत है।

KYC या अपने ग्राहक को जानें

KYC प्रॉसेस के माध्यम से बैंक, ग्राहकों को ऑथेंटिकेट और ऑनबोर्ड करते हैं और उनके अकाउंट्स खोलते हैं। डिजिटल तरीके से ऐसा करने पर यह प्रॉसेस e-KYC कहलाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल तरीके से लिए जाने वाले पर्सनल लोन का औसत आकार, मेट्रो शहरों में 2.61 लाख रुपये और गैर मेट्रो शहरों में 2.84 लाख रुपये है। इसलिए MSMEs की तत्कालीन धन आवश्यकता को पूरा करने के लिए e-KYC के जरिए मिलने वाले लोन पर 60,000 रुपये की सीमा को दस गुना बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा, ग्राहकों को e-KYC के जरिए क्रेडिट कार्ड्स लेने की इजाजत देनी चाहिए।

कई तरह से हो सकती है E-KYC

E-KYC कई तरह से किया जा सकता है। आधार OTP आधारित e-KYC एक ऐसा ही तरीका है लेकिन वर्तमान में सिर्फ बैंक ही आधार e-KYC कर सकते हैं। रेगुलेटर को यह सुविधा NBFC, HFC, AMC, इंश्योरेंस कंपनियों और सुयोग्य फिनटेक कंपनियों को भी देनी चाहिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।

वैश्विक महामारी से ठीक कुछ सप्ताह पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीडियो ख्ण्ण का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इससे बैंक डिजिटल तरीके से लाइव वीडियो के माध्यम से ग्राहकों को देख और सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यह एक ग्राहक-अनुकूल प्रक्रिया नहीं है। उम्मीद है कि समय के साथ रेगुलर इसे बेहतर बना सकते हैं।

सेंट्रल KYC रजिस्ट्री का व्यापक इस्तेमाल करने की जरूरत है। CKYC रजिस्ट्री, अकाउंट खोलने के बाद फाइनैंशलल कंपनियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले डेटा की एक रिपॉजिटरी है। रेगुलेटर को KYC मास्टर डायरेक्शन दस्तावेज में संशोधन करना चाहिए ताकि CKYC रिकॉर्ड्स का API-स्तरीय जांच को सम्पूर्ण KYC माना जा सके और अकाउंट खोलने के 10 दिन के भीतर बैंकों और NBFC कंपनियों से रजिस्ट्री में डेटा अपलोड करवाना चाहिए। रजिस्ट्री का व्यापक इस्तेमाल करने पर KYC रिकॉर्ड्स की उपयोगिता बढ़ेगी और लोन ऐप्लिकेशंस की प्रोसेसिंग ज्यादा आसान होगी।

15 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती हैं MSMEs

सरकार को अनुमान है कि 2024 तक MSMEs भारत की GDP में 50% का योगदान करने के साथ-साथ 15 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती हैं जिससे देश को अपने 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस संकट की घड़ी में उन्हें हर तरह की मदद देनी चाहिए। क्रेडिट के अनौपचारिक माध्यमों पर MSMEs की निर्भरता कम करनी होगी। यह तभी हो सकता है यदि सुयोग्य फिनटेक कंपनियों को लोन सर्विस प्रोवाइडर (LSP) लाइसेंस, और अकाउंट ऐग्रिगेटर और GSTN का लाइसेंस्ड एक्सेस दिया जाय। इससे लोन बांटने में तेजी आएगी।

हम सरकार और रेगुलेटर से क्रेडिट सप्लाई चेन को 100% कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल बनाकर, लिक्विडिटी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए ये कदम उठाने का आग्रह करते हैं। इससे सिर्फ मौजूदा चुनौतियों से ही नहीं बल्कि भविष्य में हेल्थ रिस्क का सामना करने के लिए तैयार रहने में भी मदद मिलेगी। वायरस को अभी कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन यह फिर वापस आ सकता है। हम बिना तैयारी के और अब और लम्बे समय तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते। इसलिए अब हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा और डिजिटल तरीके से काम करना होगा।

रिलायंस का राइट्स इश्यू खास, कई चीजें हो रही हैं पहली बार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस साल की शुरुआत में एक नया कारोबारी प्लैटफॉर्म शुरू किया था, जिस पर राइट्स इश्यू के योग्य शेयरधारक अपने शेयर बेच सकेंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू आज खुल गया है और सेबी के इस प्लैटफॉर्म की असली परीक्षा रिलायंस के राइट्स इश्यू के साथ होगी।

रिलायंस के राइट्स इश्यू के साथ ही RE की शुरुआत

सेबी का यह प्लैटफॉर्म कई मायनों में खास है। अब तक होता यह था कि जो शेयरधारक राइट्स इश्यू के लिए आवेदन नहीं करना चाहते थे, उनको अपने राइट एनटाइटलमेंट (RE) से वंचित होना पड़ता था या फिर इसे मुफ्त में किसी और को ट्रांसफर करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। रिलायंस के राइट्स इश्यू के साथ ही RE का कारोबार भी खुल गया है और योग्य शेयरधारक अपने RE बेच सकेंगे। यह कारोबार 29 मई को बंद कर दिया जाएगा, जबकि रिलायंस के राइट्स इश्यू में आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून रहेगी।

RE निपटान में लगता है वक्त

RE कारोबार को कुछ दिन पहले बंद करने के पीछे की वजह निपटान में लगने वाला वक्त है। RE की कारोबारी बारीकियों और सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। कारोबार के लिए नई अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN) का इस्तेमाल किया जाएगा जो सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करेगा। नए प्लैटफॉर्म के साथ रिलायंस के राइट्स इश्यू में कई और भी नई चीजे हैं जो पहली बार होने जा रही हैं।

खास बातें...

- 30 साल बाद रिलायंस राइट्स इश्यू लेकर आई है और वह भी किस्तों में।
- शेयरधारकों को हर मौजूदा 15 शेयरों पर 1257 रुपये के भाव से एक शेयर ऑफर किया जाएगा।
- इस 1257 रुपये के शेयर प्राइस में से सब्सक्रिप्शन के समय केवल 25 प्रतिशत पैसा देना होगा।
- इतनी ही रकम मई 2021 में देनी होगी। बाकी 50 प्रतिशत रकम नवंबर 2021 में चुकानी होगी।
- किस्तों में होने की वजह से अब बाजार में दो तरह के रिलायंस शेयर दिखाई देंगे, एक पूर्णतः चुकता और दूसरे आंशिक भुगतान वाले शेयर।

क्या होता है राइट्स इश्यू?

शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इश्यू लाती है। राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। राइट्स इश्यू के तहत शेयरधारक निश्चित अनुपात में ही अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी यह अनुपात तय करती है। अगर कंपनी ने राइट्स इश्यू के लिए 1:4 का अनुपात तय किया है तो इसका मतलब है कि शेयरधारक को पहले से उसके पास मौजूद हर 4 शेयर पर 1 अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका होगा। राइट्स इश्यू के लिए समय का ऐलान कंपनी करती है। तय अवधि में ही वह निवेशकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है।

कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हालात से एनबीएफसी का नकदी संकट और बढ़ने का अनुमानः मूडीज

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 संकट से जुड़े व्यवधानों के चलते गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का नकदी संकट और बढ़ सकता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे इन कंपनियों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और खराब होगी जो जिससे इन कंपनियों का नकदी संकट और गहरायेगा। मूडीज ने एक रपट में कहा कि कोविड-19 संकट के बीच लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पहले से जारी नरमी के और विकट होने की संभावना है। इसका सीधा असर एनबीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर पड़ेगा। परिसंपत्ति गुणवत्ता से आशय वितरित ऋण की ग्राहकों द्वारा उचित अदायगी से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में नरमी की वजह से लोगों की वित्तीय क्षमता प्रभावित हुई है इससे ग्राहकों के एनबीएफसी का कर्ज चुकाने में अड़चन का जोखिम भी बढ़ेगा। मूडीज की रपट के अनुसार एनबीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता बैंकों से ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि ये कंपनियां ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करातीं हैं। मूडीज के मुताबिक सितंबर 2018 में आईएलएफएस समूह के विभिन्न भुगतान दायित्वों में असफल होने के बाद एनबीएफसी का नकदी संकट बढ़ गया था। अब कोविड-19 महामारी से एनबीएफसी की यह परेशानी और बढ़ सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न ऋण किस्तों के भुगतान पर तीन महीने की रोक का विकल्प दिये जाने से निकट अवधि में एनबीएफसी की नकदी हालत और तंग हो सकती है।

मझोले उद्यमों की परिभाषा में और बदलाव किए जाएंगे: एमएसएमई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा में बदलाव की घोषणा के कुछ ही दिन बाद सरकार ने इसमें मध्यम उद्यमों की परिभाषा की और नयी समीक्षा करने का फैसला किया है। एमएसएमई मामलों के मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार मध्यम दर्जे की इकाइयों निवेश सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये और कारोबार सीमा को 200 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में कई किस्तों में जानकारी देते हुये एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव की घोषणा की थी। उसके मुताबिक कोई भी इकाई जिसमें एक करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करती है उसे सूक्ष्म श्रेणी का उद्यम माना जायेगा। इसी प्रकार 10 करोड़ रुपये का निवेश और 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाई को लघु श्रेणी की इकाई

तथा 20 करोड़ रुपये तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाई को मध्यम दर्जे की इकाई में रखा गया। एमएसएमई मंत्री ने कहा, ''हमने यह फैसला किया है कि मध्यम दर्जे की इकाई के लिये निवेश सीमा के मानदंड को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये तक ले जाया जाये और कारोबार की सीमा को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जाये। इसके लिये हम आदेश जारी करेंगे।'' वह एक निर्यातक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि उनके मुताबिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाइयों के लिये तय किये गये मानदंड निवेश अथवा कारोबार के आधार पर तय होने चाहिये। यह निवेश और कारोबार दोनों के आधार पर नहीं होने चाहिये जैसा कि घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे जल्द ही ठीक करेगी। गडकरी ने कहा कि वह मध्यम इकाइयों के लिये कारोबार सीमा को 250 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के सुझाव पर विचार को तैयार है और इस मुद्दे को वह एमएसएमई सचिव के साथ भी साझा करेंगे।

एमएसएमई मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना देश के निर्यात कारोबार में एमएसएमई के योगदान को मौजूदा 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के देश की जीडीपी में योगदान को 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है। निर्यातक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ''हम देश में पांच करोड़ नये रोजगार पैदा करने की योजना बना रहे हैं। अब तक हमने 11 करोड़ रोजगार सृजित किये हैं'' उन्होंने कहा कि वह भारतीय एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निर्यातकों को वर्तमान समय का लाभ उठाना चाहिये जब पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है, उन्हें लागत कम करके और आयात सामान का विकल्प तैयार करना चाहिये।

सैलरी वालों समेत 3 कैटेगरी को नहीं मिलेगा TDS दर की कटौती का फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक कैश पहुंचाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को टीडीएस (tax deducted at source) और टीसीएस (tax collection at source) में 25 फीसदी की कटौती की घोषणा की। TDS और TCS के जरिए लोगों की आय पर टैक्स काटा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार की आय बनी रहे और टैक्स चोरी पर भी नजर रखी जा सके। हालांकि, इसमें भी कुछ कैटेगरी हैं, जिन्हें इस कटौती का फायदा नहीं मिलेगा।

1- पैन या आधार देना है जरूरी, वरना फायदा नहीं

अगर कोई शख्स टैक्स डिडक्टर को पैन या आधार मुहैया नहीं कराता है तो उस पर 20 फीसदी या अधिक का टैक्स बोझ पड़ सकता है। यानी अगर आप पैन या आधार मुहैया नहीं कराते हैं तो समझ लीजिए कि टीडीएस-टीसीएस कटौती का फायदा आपके लिए नहीं है।

2- सैलरी वालों के लिए नहीं है ये घोषणा

सैलरी पर टीडीएस टैक्स स्लैब रेट के आधार पर कटता है, इसलिए ये राहत सैलरी वालों के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी पर पहले की दर पर ही टीडीएस कटेगा, ना कि आपको निर्मला सीतारमण की घोषणा का फायदा मिलेगा।

3- प्रवासी भारतीयों को फायदा नहीं

एक और अहम बात ये है कि टीडीएस-टीसीएस कटौती का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो भारत में रहने वाले हैं, प्रवासी भारतीय टैक्सपेयर इसका फायदा नहीं ले सकते।

31 मार्च 2021 तक मिलेगा फायदा

टीडीएस और टीसीएस की घटी दरें 14 मई से प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। टीडीएस की दरें 1 फीसदी से 30 फीसदी तक हो सकती हैं। दर कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आय का सोर्स क्या है। वहीं दूसरी ओर टीसीएस की दरें 0.10 फीसदी से 5 फीसदी तक हो सकती हैं।

स्वदेशी जागरण मंच ने स्थानीय उद्योगों, उत्पादों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 'लोकल के लिए वोकल (स्थानीय उत्पादों का समर्थन करिए)' का मंत्र दिये जाने कुछ दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की मंगलवार को घोषणा की। एसजेएम ने कहा कि वह आयातित वस्तुओं के विकल्प के तौर पर स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की सूची बांटेगा । उसने घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात शुल्क ढांचे में बदलाव की भी मांग की। कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल की पैरवी संबंधी मोदी के भाषण का हवाला देते एसजेएम संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, '' यह वैश्वीकरण एवं उदारीकरण खासकर विकास के विदेशी पूंजी आधारित मॉडल पर आधारित वर्तमान नीति से सुखद विदाई है।'' उन्होंने कहा कि अपने 'स्वदेशी स्वालंबन अभियान' से मंच देश में'स्वदेशी' एवं आत्मनिर्भरता के महत्व पर जागरूकता पैदा करेगा। महाजन ने कहा कि आत्मनिर्भरता छोटे उद्योगों, छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और ग्रामीण उद्योगों समेत स्वदेशी उद्योग में जान फूंककर हासिल किया जा सकता है और उसका लक्ष्य रोजगार सृजन में रफ्तार के साथ ही समावेशी वृद्धि हो। देश में आयातित उत्पादों पर निर्भरता के लिए अतीत के नीति-नियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने स्वदेशी मेधा, संसाधनों और ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं किया तथा विदेशी पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अत्यधिक बल दिया। महाजन ने कहा, '' हम स्थानीय मेधा, संसाधनों, ज्ञान, उद्यमिता और मानव मूल्यों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सभी देशभक्त नागरिकों एवं उद्योग से इस स्वदेशी स्वालंबन अभियान ' से उत्साह से जुड़ने का आह्वान करते हैं।''

एसोचैम का अंतरराज्यीय आवागमान की अनुमति देने का आग्रह

नयी दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को राज्यों की सीमाओंसे प्रतिबंध हटाकर लोगों को एक राज्य दूसरे राज्य में आने जाने में राहत देने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने राज्यों से कहा है कि उन्हें लॉकडाउन चार के दौरान राज्यों के बीच निजी वाहनों से आवागमन में ढील दी जानी चाहिये। उद्योग मंडल ने कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के लिये लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने की भी मांग की है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा है, ''कई राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों को आने से रोक रहे हैं। पर आज स्थिति यह है कि यदि कोई महानगर एक राज्य में है तो उसके उप-नगर, जो कारपोरेट कार्यालयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तरों के बड़े केन्द्र बनकर उभर रहे हैं, दूसरे राज्य में पड़ते हैं।'' सूद ने कहा कि बड़ी संख्या में कंपनियों के कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं, ज्यादातर कंपनियां इसी तरह काम कर रही है लेकिन इन कंपनियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिये कुछ कर्मचारियों को दफ्तर में अथवा दूसरे कार्यस्थलों पर भी रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में छूट दिये जाने की भावना के विपरीत कुछ राज्य लोगों के आवागमन से रोक रहे हैं। सूद ने कहा कि लॉकडाउन के पिछले 56 दिनों के दौरान सरकार को काफी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तमाम आंकड़े जुटाये जा चुके हैं और हॉट स्पॉट तथा अन्य संवेदनशील इलाकों की पहचान हो चुकी है। ऐसे में बाकी क्षेत्र से लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जना चाहिये। इस मामले में सीमा से लगते राज्यों के बीच बेहतर समझ होनी चाहिये।

औद्योगिक संगठनों का ई- धरना आंदोलन को आईपीपीएफ का समर्थन

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस ई धरना आंदोलन में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, मप्र प्लास्टिक ग्रेनुअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, मालवा चेम्बर्स ऑफ कामर्स, ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सहित अनेक संगठनो का समर्थन मिला है।

जुडेंगे प्रदेश के औद्योगिक संगठन

एआईएमपी उपाध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने बताया कि इस ई-धरना आंदोलन को जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है। इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी ने उद्योग की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। वही प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर संभाग के प्रभारी श्री तुलसी सिलावट ने भी उद्योगों की बिजली बिल संबधी मांग पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। एआईएमपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जैन भटेवराने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के बाद लगभग सभी उद्योग 5 मिनिट भी नही चले है लेकिन उनके बिजली के बिल लाखों में आ रहे है। ये बिल उद्योगों को मारने के जैसे है। उन्होनें कहा कि अप्रैल और मई माह में कोई उत्पादन नही होने के बाद भी विद्युत बिल में फिक्स चार्ज, न्यूनतम युनिट्स और पॉवर फैक्टर के चलते लाखों रूपए के बिल आ रहे है। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि औद्योगिक संगठनों ने बिजली कंपनी सीएमडी, डिस्कॉम कंपनी और इलेक्ट्रिक सिटी रेग्युलेटरी और प्रमुख सचिव उर्जा को भी पत्र लिखें है लेकिन कोई हल नही निकला है। ऐसे में अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुचानें के लिए प्रदेश के सभी संगठन ई-धरना देगें। यदि शासन उद्योगों को राहत नही देगा को कई उद्योग स्थाई रूप से बंद हो जाएगें। इस दिशा में देश के 8 राज्यों ने समय पर एक्शन लेकर वहां के उद्योगों को बचाने के लिए काम किया है।

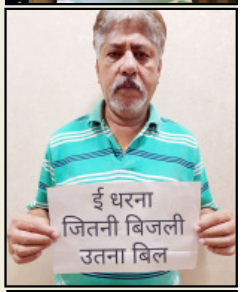

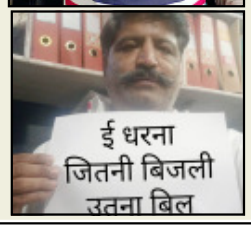

बंद उद्योगों के लाखों के बिल

उद्योगपतियों का कहना है कि फिक्स चार्जेस जो कि जितना किलोवाट का विद्युत संयोजन है उतना भुगतान करना पडता है। यह 33 केवी के कनेक्शन पर 560 रूपए प्रति किलो वॉट का शुल्क लिया जाता है जोकि लॉकडाउन अवधि में इसका लिया जाना सरासर गलत है। न्युनतम युनिट्स जो प्रतिमाह उपभोग करना जरूरी है वो लॉकडाउन में उद्योग बिजली उपभोग नही कर पाये उसका भी शुल्क विद्युत कंपनी द्वारा लिया जा रहा है। इसे पुरा समाप्त करने की मांग की जा रही है। वही पॉवर शस्ति फैक्टर शुल्क बंद उद्योगों में लाईन लॉस का शुल्क है। बंद उद्योग में पावर फेक्टर संभाल पाना असंभव है, इसे उद्योग संचालित करते हुए संभाला जा सकता है। इससे भी छूट की मांग भी की जा रही है। यह तीनों शुल्क लगाकर विद्युत वितरण कंपनीयों द्वारा जो बिल उद्योगों को जारी किये गये है वे अव्यावहारिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ धोखाधडी है।

EPF अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान को जुलाई तक तीन महीनों के लिए मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 10 प्रतिशत करने के निर्णय को लागू कर दिया है।

इस फैसले से संगठित क्षेत्र के 4.3 करोड़ कर्मचारी घर अधिक वेतन ले जा सकेंगे और कोरोना वायरस महामारी के चलते नकदी संकट से जूझ रहे नियोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। अनुमान है कि इस निर्णय से अगले तीन महीनों में 6,750 करोड़ रुपये की नकदी बढ़ेगी। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि ईपीएफ योगदान में कमी मई, जून और जुलाई, 2020 के महीनों के लिए लागू होगी। ऐसे में जून, जुलाई और अगस्त में मिलने वाला वेतन अधिक होगा और नियोजकों के योगदान में भी कमी आएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक बढ़ा, निफ्टी ने 8,950 का स्तर छुआ

मुंबई। एजेंसी

प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 300 अंकों से अधिक की तेजी हुई और इस दौरान मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच आईटीसी, एचडीएफसी और एचयूएल में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 30,524.53 के ऊपरी स्तर को छूने के बाद 217.69 अंक या 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 30,413.56 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएसई निफ्टी 57.70 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 8,936.80 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक तीन प्रतिशत की बढ़त आईटीसी में हुई। इसके अलावा एलएंडटी, टाटा स्टील, एनटीपीसी, एचयूएल, पावरग्रिड, एचडीएफसी और अल्ट्राटेक सीमेंट भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और एसबीआई में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को पूंजी बाजार से 1,328.31 करोड़ रुपये के निकाले। विश्लेषकों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण कारोबारी सतर्क रुख अपना रहे हैं।

कोविड-19 से 6 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंसेंगे

100 देशों को 160 अरब डॉलर की सहायता:विश्वबैंक

वाशिंगटन। एजेंसी

विश्वबैंक ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक लोग निपट गरीबी के दलदल में फंसेंगे। इस वैश्विक निकाय ने इस वैश्विक संकट से उबरने के अभियान के तहत 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। यह पूरी सहायता पंद्रह महीने की अवधि में दी जाएगी। विश्वबैंक के अध्यक्ष डेविड मालपॉस ने एक कांफ्रेन्स कॉल में संवाददाताओं से कहा, "इस महामारी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बंद होने से 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की दलदल में फंस जाएंगे। हाल के दिनों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में हमने जो प्रगति की है, उसमें से बहुत कुछ खत्म हो जाएगा।' उन्होंने कहा, "विश्वबैंक समूह ने तेजी से कदम उठाया है और 100 देशों में आपात सहायता अभियान शुरू किया है। इसमें अन्य दानदाताओं को कार्यक्रम के तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति होती है।" उन्होंने कहा कि 160 अरब डालर की राशि 15 माह में दी जाएगी। वश्वबैंक से सहायता पा रहे इन 100 देशों में दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी रहती है। इनमें से 39 अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र के हैं। कुल परियोजनाओं में एक तिहाई अफगानिस्तान, चाड, हैती और नाइजर जैसे नाजुक और चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में हैं। मालपॉस ने कहा, "वृद्धि के रास्ते पर लौटने के लिये हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य आपात से निपटने को लेकर तीव्र और लचीला रुख होना चाहिए। साथ ही गरीबों की मदद के लिये नकद और अन्य सहायता, निजी क्षेत्र को बनाये रखना तथा अर्थव्यवस्था की मजबूती और पुनरूद्धार को मजबूत बनाना होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को देशों के हिसाब से तैयार किया है ताकि वे स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक झटकों से प्रभावी तरीके से निपट सके जिसका वे सामना कर रहे हैं। मालपॉस ने कहा कि इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों की खरीद में मदद मिलेगी।

विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तारीखों घोषित

मुम्बई। आईपीटी नेटवर्क

एशिया के अग्रणी फ़िल्म, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव आर्ट इंस्टीट्यूट विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल (WWI) ने 2020 में दाखिले के लिए तीसरे दौर की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। WWI के पूर्ण कालिक डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन क्रमशः 22, 23 और 26 मई, 2020 को बंद हो जाएंगे। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल प्रोफेशनल तौर पर सामाजिक कार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मशहूर एशिया के सबसे पुराने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (TISS) द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेस में शिक्षा प्रदान करता है। वैश्विक महामारी से उपजे खतरे के मद्देनजर कोर्सेस के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। 22 मई, 2020 से BSc/BA फिल्म में किंग। फिल्म मे किंग में एडवांस्ड डिप्लोमा। BA स्क्रीन राइटिंग। स्क्रीन राइटिंग में डिप्लोमा और 23 मई, 2020 से BA म्यूजिक प्रोडक्शन ऐंड कम्पोजिशन। BA एक्टिंग। एक्टिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा। BBA मीडिया ऐंड कम्युनिकेशन। मीडिया में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा ऐंड एंटरटेनमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम ऐंड एक्सपीरियंशल मार्केटिंग प्रवेश प्रारंभ होगा। 26 मई, 2020 से इंटीग्रेटेड BSc/BA + एनिमेशन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा। इंटीग्रेटेड BSc/BA + गेम डिज़ाइन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा। इंटीग्रेटेड BSc/BA + विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा। फ़ैशन डिज़ाइन में BA में प्रवेश प्रारंभ होगा। फोर्ब्स इंडिया द्वारा WWI को देश के सबसे प्रभावशाली इंस्टीट्यूट का खतिब हासिल है। इस समय WWI के 2200 से भी अधिक पूर्व छात्र देश और दुनिया भर के विभिन्न मीडिया संस्थानों, फ़िल्म निर्माण? कंपनियों और फ़ैशन हाउसेज़ में कार्यरत हैं। इस संस्थान का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके तहत थ्योरी के साथ-साथ छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव भी प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा छात्रों को तमाम तरह की शिक्षा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखनेवाले शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे में इस संस्थान के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के विश्व स्तरीय ग्रेजुएट छात्र तैयार हो रहे हैं।

सरकार के खरीद पोर्टल जेम में आदिवासी समुदाय के बनाए 4,316 उत्पाद शामिल

नयी दिल्ली। सरकारी विभाग, एजेंसी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अब सरकार के खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जेम) से आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीद सकते हैं। जेम ने आदिवासी समुदाय के बनाए 4,000 से अधिक उत्पादों को अपने पोर्टल में शामिल किया है, जिसमें चित्रकारी, कलात्मक वस्तुएं और मूर्तियां शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त 2016 में सरकारी खरीद के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जेम की शुरुआत की थी। जेम के सीईओ तल्लीन कुमार ने कहा, "भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने 48 विभिन्न श्रेणियों में 4,316 उत्पादों को अपलोड किया है, जिसमें चित्र, हस्तनिर्मित शोपीस, मूर्तियां, हस्तशिल्प और बैग शामिल हैं।"

शनि देव से डरें नहीं उन्हें समझे....

22 मई को शनि जयंती

हम आपको बताते हैं कि शनि से डरना नहीं बल्कि उन्हें समझने से ही हम उनकी मार से बच कसते हैं। देवता और भगवान सभी को शनि की वक्र दृष्टि को सहना पड़ा है तो मनुष्य की बिसात क्या। अतः शनि से बचने का एक मात्र तरीका आप जान लीजिए।

शनिदेव का का परिचय : इन्हें यमाग्रज, छायात्मज, नीलकाय, क्रुर कुशांग, कपिलाक्ष, अकैसुबन, असितसौरी और पंगु इत्यादि कहा जाता है। इनके सिर पर स्वर्णमुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनीलमणि के समान। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं।

शनि ग्रह की शक्ति : इस ग्रह के देवता लाल किताब के अनुसार भैरवजी और परंपरागत ज्योतिष के अनुसार शनिदेव हैं। इनका गोत्र कश्यप, जाति क्षत्रिय, रंग श्याम, नीला, वाहन गीद्ध, भैंसा, कौवा, दिशा वायव, वस्तु लोहा, फौलाद, पोशाक जुराब, जूता, पशु भैंस या भैंसा, वृक्ष कीकर, आक और खजूर का वृक्ष, राशिः बुध, शुक्र, राहु मित्र। सूर्य, चंद्र और मंगल शत्रु और बृहस्पति समय। भ्रमण काल एक राशि में अढ़ाई वर्ष। नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रपद, शरीर के अंगों में दृष्टि, बाल, भवें, कनपटी, पेशा लुहार, तरखान और मोची, सिफतः मूर्ख, अक्खड़, कारिगर, गुण देखना, भालना, चालाकी, मौत और बीमारी, शक्ति जादूमंत्र देखने दिखाने की शक्ति, मंगल के साथ होतो सर्वाधिक बलशाली शनि देव मकर और कुम्भ राशी के स्वामी है। तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना गया है। ग्यारहवां भाव पक्का घर। दसवें और अष्टम पर भी आधिपत्य।

कर्म होता संचालित : शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता तथा राज्य का भाव माना गया है। एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है।

न्यायाधीश है शनि : मान्यता है कि कुंडली में सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति, शनि है न्यायाधीश, राहु-केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, शुक्र है-पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल-चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं।

शनि को यह पसंद नहीं : भगवान शनि को पसंद नहीं है जुआ-सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, परस्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा-चाची, माता-पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद हवा को मुक्त करना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना। सफाईकर्मी और अपंगों का अपमान करना आदि। शनि के मूल मंदिर जाने से पूर्व उक्त बातों पर प्रतिबंध लगाएं।

अशुभ की निशानी : शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षति ग्रस्त हो जाता है, नहीं तो कर्ज या लड़ाई-झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं। अचानक आग लग सकती है। धन, संपत्ति का किसी भी तरह नाश होता है। समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी। झूठे इल्जाम लगने लगते हैं। यदि व्यक्ति अपना चाल चलन ठीक नहीं रखता है जेल या फांसी तक हो सकती है।

फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है। रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है। पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना। सिर की नसों में तनाव। अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है।

शुभ की निशानी : शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान-सम्मान खूब रहता हैं। उस व्यक्ति के कोई शत्रु नहीं होते हैं और वह सभी से सहयोग प्राप्त करता है।

उपाय : सर्वप्रथम भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ, और जूता दान देना चाहिए। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलावे। छायादान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा-सा सरसो का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापो की क्षमा मांगते हुए रख आएं। दांत साफ रखें। अंधे-अपंगों, सेवकों और सफाईकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। अतः में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़कर शनि देव को जो पसंद नहीं है उसका पालन करता रहता है तो भगवान शनिदेव उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं।

सावधानी : कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो भिखारी को तांबा या तांबे का सिक्का कभी दान न करें अन्यथा पुत्र को कष्ट होगा। यदि आयु भाव में स्थित हो तो धर्मशाला का निर्माण न कराएं। अष्टम भाव में हो तो मकान न बनाएं, न खरीदें। उपरोक्त उपाय भी लाल किताब के जानकार व्यक्ति से पूछकर ही करें।

ये उपाय शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए

- आपत काल में भी शनिदेव का दर्शन करो।
- दुखद वक्त में भी शनिदेव पर विश्वास करो।
- जीवन के हर्षित पल में भी शनिदेव कि प्रशंसा करो।
- मुश्किल पीड़ादायक वक्त में भी शनिदेव कि पूजा करो।
- जीवन के हर पल में शनिदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो।

9 ग्रहों की 9 सुगंध से पाएं चमत्कारिक लाभ

सुगंध का हमारे जीवन और वातावरण में बहुत ही महत्व होता है। सुगंध से मानसिक शांति मिलती है। कई रोगों में सुगंध से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव को सुगंध के द्वारा अच्छे प्रभाव में बदला जा सकता है। तो जानिए कि कैसे सुगंध से ग्रहों की शांति की जा सकती है।

1. **सूर्य ग्रह :** यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप केसर या गुलाब की सुगंध का उपयोग करें। घर के लिए होम प्रेशनर लाएं और शरीर के लिए इस सुगंध का कोई इत्र उपयोग करें।
2. **चंद्र ग्रह :** चंद्रमा मन का कारण है अतः इसके लिए चमेली और रातरानी के इत्र का उपयोग कर सकते हैं।
3. **मंगल ग्रह :** मंगल ग्रह की परेशान से मुक्त होने के लिए लाल चंदन का इत्र, तेल अथवा सुगंध का उपयोग कर सकते हैं।
4. **बुध ग्रह :** बुध ग्रह की शांति के लिए चंपा का इत्र तथा तेल का प्रयोग बुध की दृष्टि से उत्तम है।
5. **गुरु ग्रह :** केसर और केवड़े के इत्र के उपयोग के अलावा पीले फूलों की सुगंध से गुरु की कृपा पाई जा सकती है।
6. **शुक्र ग्रह :** शुक्र को सुधारने के लिए सफेद फूल, चंदन और कपूर की सुगंध लाभकारी होती है। चंपा, चमेली और गुलाब की तीक्ष्ण खुशबू से खराब हो जाता है।
7. **शनि ग्रह :** शनि के खराब प्रभाव को अच्छे प्रभाव में बदलने के लिए कस्तुरी, लोबान तथा सौंफ की सुगंध का उपयोग कर सकते हैं।
8. **राहु और 9. केतु छाया ग्रह :** काली गाय का घी व कस्तुरी के इत्र का उपयोग कर राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। यही यह कहीं से उपलब्ध न हो तो घर के शौचालय को साफ सुधरा रख कर घर में प्रतिदिन कर्पूर जलाएं। गुड़ और घी को मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं।

स्वस्ति वाचन से होता है जीवन में मंगल और शुभता का आगमन, देवता होते हैं जाग्रत

हम सभी जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, प्रतिदिन आरती पूजा करते हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि हर पूजन से पहले यह स्वस्ति वाचन करना चाहिए। यह मंगल पाठ सभी देवी-देवताओं को जाग्रत करता है।

ॐ शांति सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्ति भवतु। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातापितृ चरण कमलभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थान देवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वे देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्यहा गणाधिपतये नमः।

इस पाठ से जीवन में शुभता और मंगल का आगमन होता है। पूजा से पहले इसके वाचन का यही उद्देश्य है कि समस्त देवी-देवता आपकी पूजा को ग्रहण करने के लिए और पूजा का शुभ प्रतिफल देने के लिए तैयार और तत्पर हो जाए।

विदेशी निवेशकों ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से 26 अरब डॉलर

सिर्फ भारत से 16 अरब डॉलर निकाले

वाशिंगटन। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच विदेशी निवेशकों ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से लगभग 26 अरब अमरीकी डालर और भारत से 16 अरब अमरीकी डालर निकाले। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। अमेरिकी कांग्रेस के स्वतंत्र शोध केंद्र ने कोविड-19 के वैश्विक आर्थिक प्रभावों के बारे में अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, ''विदेशी निवेशकों ने विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से लगभग 26 अरब डॉलर और भारत से 16 अरब डॉलर से अधिक राशि बाहर निकाली।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली में तीन करोड़ से अधिक लोगों ने सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यूरोक्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 3.8 प्रतिशत की कमी हुई है, 1995 से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2020 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं कोरोना वायरस के प्रकोप से नुकसान में हैं, लेकिन केवल तीन देशों चीन, भारत और इंडोनेशिया की विकास दर 2020 में सकारात्मक रहने का अनुमान है।

औद्योगिक क्षेत्रों में काम शुरू, श्रमिकों की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे मुद्दे उठे

नयी दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण में विभिन्न कार्यों के लिये दी गई छूट के साथ ही दिल्ली में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं। लेकिन इसके साथ ही उनके सामने श्रमिकों की कमी और आपूर्ति श्रृंखला बिखराव दिखाई दिया। दिल्ली सरकार ने 18 मई से 31 मई के दौरान लॉकडाउन के चौथी चरण में औद्योगिक कारखानों को अलग अलग समय सीमा के साथ काम करने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 'ए' से लेकर 'एल' नाम से शुरू होने वाली औद्योगिक इकाइयों में प्रातः साढे सात बजे से लेकर सांय साढे पांच बजे तक काम होगा जबकि 'एम' से 'जैड' नाम से शुरू होने वाली औद्योगिक इकाइयां प्रातः साढे आठ बजे से लेकर सांय साढ़े छह बजे तक काम करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन के विस्तार के साथ ही कुछ रियायतें देने की घोषणा की। उनकी घोषणा के बाद मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 1,100 इकाइयों में से करीब 300 ने मंगलवार को काम किया। मायापुरी रेवाड़ी लाइन औद्योगिक संघ के महासचिव आर के गुप्ता ने कहा कि स्थिति में तब तक सुधार आना मुश्किल है जब तक कारखाना संचालन से जुड़ी पूरी श्रृंखला -- कच्चा माल, विनिर्माण, परिवहन, श्रमिक और बाजारों-- में काम शुरू नहीं हो जाता है। एक अन्य औद्योगिक क्षेत्र उद्योग नगर में भी 550 में से करीब एक चौथाई इकाइयों ने काम शुरू किया है। पश्चिम दिल्ली स्थिति इस औद्योगिक क्षेत्र में चप्पल, जूते, इंजीनियरिंग सामान तैयार किया जाता है।

निर्मला सीतारमण ने बताया आखिर मोदी सरकार ने क्यों लोगों को नहीं दिया कैश

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना के मद्देनजर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद कई दिनों तक रोज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के हर हिस्से को विस्तार से समझाया कि किसे क्या मिला। उसी को ध्यान में रखते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई ने निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू लिया और कुछ सवाल पूछे। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या बातें कहीं।

कैश ट्रांसफर पर क्या बोलीं निर्मला

निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के बाद पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत मोदी सरकार ने कैश ट्रांसफर किया। हालांकि, उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बंद नहीं किए। उन्होंने आगे कहा कि कैश ट्रांसफर करने के लिए हमने जो तरीका सोचा वह कहीं अधिक प्रभावी है। इसका अधिक से अधिक फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बैंकों, बिजनेस और वर्किंग कैपिटल के लिए दिए गए पैसों के जरिए लोगों को सहायता देने का फैसला किया।

भारत ने चार महीने बाद मलेशिया से शुरू किया पाम ऑयल आयात, ये है वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने जनवरी में मलेशिया से तेल के आयात पर रोक लगा दी थी। इसे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के भारत की नीतियों के खिलाफ हमलावर होने से जोड़कर देखा जा रहा था। महातिर कश्मीर मुद्दे से लेकर नागरिकता कानून को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। करीब चार महीनों तक रोक के बाद अब भारत ने फिर से मलेशिया से पाम ऑयल का आयात शुरू कर दिया है। करीब चार महीनों तक रोक के बाद अब भारत ने फिर से मलेशिया से पाम ऑयल का आयात शुरू कर दिया है। भारत और मलेशिया में कुछ राजनयिक तनाव के बाद यह आयात रोक दिया गया था।

क्यों रुका था आयात

भारत ने जनवरी में मलेशिया से तेल के आयात पर रोक लगा दी थी। इसे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के भारत की नीतियों के खिलाफ हमलावर होने से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें कि महातिर कश्मीर मुद्दे से लेकर नागरिकता कानून तक, भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं।

इस तरह शुरू हुआ आयात

मलेशिया में नई सरकार चुने जाने के बाद भारत और मलेशिया के कारोबारी रिश्तों में सुधार हुआ है। पिछले हफ्ते मलेशिया ने भारत से रिकॉर्ड 1 लाख टन चावल की खरीद का सौदा किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसके बाद एक प्रमुख भारतीय निर्यातक ने मलेशिया से 2 लाख टन क्रूड पाम ऑयल आयात का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह ऑर्डर जून और जुलाई में भेजा जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक 2020 के पहले चार महीनों में भारत का कुल पाम ऑयल आयात साल 2019 के इसी अवधि के मुकाबले 50 फीसदी से भी कम हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल निर्यातक है और हाल के दिनों में वहां कीमत 10 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गई थी।

भारत दुनिया भर में खाद्य तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के कुल खाद्य तेल के आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी दो-तिहाई है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है जिसमें ज्यादातर तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से ही आता है। इन देशों के अलावा भारत अर्जेंटीना और ब्राजील से सोया तेल और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल भी खरीदता है।

लॉकडाउन के दौरान दुनियाभर में कार्बन उत्सर्जन में आई 17 प्रतिशत तक की गिरावट

केंसिंग्टन। एजेंसी

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण पिछले महीने दुनियाभर में कार्बन डाइऑक्साइड के रोजाना होने वाले उत्सर्जन में 17 प्रतिशत तक की कमी आई। एक नए अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जनजीवन सामान्य होगा तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रदूषण में थोड़े समय के लिए आई यह कमी ''समुद्र में एक बूंद के समान'' होगी। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अध्ययन में वैज्ञानिकों की टीम ने आकलन किया कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और इस साल यह चार से सात प्रतिशत के बीच रहेगा जो 2019 के स्तर से कम है। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। अगर लॉकडाउन संबंधित सख्त नियम दुनियाभर में पूरे साल बने रहते हैं तो प्रदूषण के स्तर में सात प्रतिशत तक की कमी आएगी और अगर उन्हें जल्द ही हटा दिया जाता है तो यह गिरावट चार प्रतिशत ही होगी। अप्रैल में एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्तर में एक तिहाई तक कटौती की। विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक चीन ने फरवरी में कार्बन प्रदूषण में करीब एक चौथाई तक कटौती की। भारत और यूरोप ने क्रमशः 26 और 27 प्रतिशत तक की कटौती की। यह अध्ययन मंगलवार को पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुआ।

जर्मनी की फुटवियर कंपनी चीन से आगरा लाएगी अपना कारखाना

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 महामारी के बीच जर्मनी की फुटवियर कंपनी कासा ऐवर्ज जिम्ब ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने की घोषणा की है। कंपनी वहां सालाना 30 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन करती है। इसके लिए उसने घरेलू जूता निर्यातक कंपनी आईआट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है।कंपनी शुरुआत में 110 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वॉन वैलेक्स ब्रांड नाम से जूते बनाने वाली कासा ऐवर्ज जिम्ब यह कारखाना उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित होगा। आईआट्रिक इंडस्ट्रीज के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जैन ने एक ईमेल के माध्यम से पीटीआई-भाषा से कहा, '' कई दौर की बातचीत के बाद कासा ऐवर्ज ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने का निर्णय किया है।'' कासा ऐवर्ज की चीन में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। इन दोनों इकाइयों में सालाना 30 लाख जोड़ी से अधिक जूते तैयार होते हैं।

आईआट्रिक इंडास्ट्रीज के पास पहले से कासा ऐवर्ज के वोन वेलेक्स जर्मनी के '5 जोन' ब्रांड के महिला और पुरुषों के सालाना पांच लाख जोड़ी जूते बनाने की क्षमता है। इसके अलावा कंपनी के पास पांच लाख जोड़ी जूते बनाने की क्षमता वाला एक अलग संयंत्र भी है। उन्होंने कहा कि एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 30 लाख जोड़ी जूतों से अधिक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से सभी अनिवार्य सहयोग मिलने के बाद कंपनी दो साल में इस विनिर्माण क्षमता को प्राप्त कर लेगी। कासा ऐवर्ज का जूता दुनिया के 80 देशों में पेटेंट है। यह जूता पैर, घुटने और कमर के दर्द में राहत पहुंचाता है। जोड़ों और मांसपेशियों की सुरक्षा करता है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। कंपनी मधुमेह के मरीजों के लिए भी विशेष फुटवियर भी बनाती है। भारत में यह गत वर्ष पेश किया गया जो अभी देशभर में 500 से अधिक शोरूम और ऑनलाइन उपलब्ध है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के हवाले से कहा कि उनके लिए खुशी की बात है कि जर्मनी की कंपनी भारत के आगरा शहर में आ रही है। सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। कंपनी का दावा है कि इससे 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

Authorised Dealer of

Reliance
POLYMERS

Bhaskar Resins Pvt Ltd

DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD

44 D-2, Sanwer Road Industrial Area, Sector D, Railway Crossing Main Rd, Indore, Madhya Pradesh 452015
website- http://bhaskarresins.com
email- bhaskarresins12@gmail.com

Mob- +91-96307-98864
Tel : 0731 -2971277, 2971377
email- sachinbansal123@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।